SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Why should he presume that I am misled?

MR. SPEAKER: Order, order. Next question.

Shortage of Telephone Equipment

+

*904. SHRI JAI SINGH:
SHRI HARDAYAL DEVGUN:
SHRI YAJNA DATT SHARMA:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the supply of telephones is more than five years behind the demand for the country as a whole;

(b) whether it is also a fact that the gap between the demand and the supply of the telephones is progressively increasing;

(c) whether it is also a fact that the telephone communication constitutes a vital part of the country's infra-structure; and

(d) whether it is also a fact that the Indian Telephone Industries, Bangalore is exporting the telephones equipment in large quantities; and if so, the reason therefor while the country is facing acute shortage of these items?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) नया टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए समूचे देश में प्रतीक्षा की औसत अवधि 4.6 वर्ष है। इस प्रकार मांग और मांग की पूर्ति करने के बीच लगभग 5 वर्ष के समय का अन्तर है।

(ख) जी हां। 1964 में नए टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची पर लगभग 2.6 लाख नाम दर्ज थे। 30 सितम्बर, 1969 को यह संख्या बढ़कर लगभग 4.4 लाख हो गई है।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां, परन्तु बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं। आई० टी० आई० के कुल उत्पादन का केवल 3.84 प्रतिशत ही मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए बाहर निर्यात किया गया है।

SHRI JAI SINGH: May I know what is the target in this regard in the fourth Five Year Plan, and if the Government are reasonably certain of achieving the target?

SHRI SHER SINGH: The target for the fourth Five Year Plan is six lakhs for the telephones and it will come to 7.6 lakh telephone sets in the country.

SHRI JAI SINGH: Are you reasonably certain of achieving the target?

SHRI SHER SINGH: Yes, Sir. We are reasonably cértain.

MR. SPEAKER: Are you reasonably assured? Shrí Devgun—absent. Shri Yajna Datt Sharma.

श्री यज्ञ दत्त शर्मा: मंत्री महोदय की यह जानकारी में होगा कि इस संयंत्र की कमी के कारण या टेलीफोन में काम में आने वाले उपकरणों की कमी के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं। लुधियाना जैसे नगर में जिस ढंग से वहां के व्यापार का और वहां के उद्योग का विस्तार हुआ है, आज भी वहां पर स्वचालित सिस्टम नहीं है, आटोमेटिक एक्सचेंज सिस्टम नहीं है और उस के कारण से काम में लगने वाले समय सारे साधन और शक्ति, उस की कितनी बड़ी हानि हो रही है इस का एक मोटा अंदाजा आप को होगा।

इस के अतिरिक्त मैं एक दूसरी कठिनाई की ओर ध्यान खींचना चाहता हूं कि औपरेटिंग सिस्टम जिस पर आज उन्हें डिपेंड करना पड़ रहा है उस के कारण नित्य प्रति कितनी कठिनाइयां पेश आती है क्योंकि आखिर उन लोगों के काम के दबाव के कारण वह काम करने सम्बन्धी तमाम कठिनाइयां हैं...

अध्यक्ष महोदय: आप सीधा सवाल करें।

श्री यज्ञ दत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्पष्टीकरण करने की अत्यन्त आवश्यकता है और मैं आप को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं सदन का समय व्यर्थ में नहीं ले रहा हूं। मैं आप को आज बतलाता हूं कि आपरेटर्स के बारे में लगातार शिकायतें होती हैं और उन को बराबर यह कहा जाता है कि वह गैर-जिम्मेदार हैं। वह काम को निभाते नहीं लेकिन मुश्किल यह है कि काम का दबाव इतना ज्यादा है, मानवी शक्ति की सीमाएं हैं, उस नाते से मैं यह कहनां चाहता हूं कि यह टकराव आ रहा है, उस को दूर करने के लिए जो इस प्रकार के स्थानों पर आटोमेटिक एक्सचेंज सिस्टम लगाने की ओर इस के अतिरिक्त गांवों के बाक़ी स्थानों पर जो छोटे छोटे एक्सचेंज बनाने की आवश्यकताएं हैं उन के ऊपर आप क्या ध्यान दे रहे हैं? पंजाब के जो उद्योग केन्द्र है, जैसे बटाला है, जैसे लुधियाना है, पटियाला है, इन स्थानों के ऊपर आप आटोमेटिक एक्सचेंज सिस्टम कितनी जल्द से जल्द शुरू कर रहे हैं? कृपया समय की मुझे अवधि बतलाइये।

श्री शेर सिंह : यह ठीक है कि कठिनाइयां है और उस के कारण टेलीफोन कनैक्शन देने में देर भी होती है परन्तु उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम बाहर से जितने उपकरण मंगवा सकते हैं उस का भी हम यत्न करते हैं और अपने देश में भी जितने बना सकते हैं उन के बनाने का भी हम यहां पर यत्न कर रहे ह।

एककठिनाई यह भी है कि जितने टेलीफोन हम यहां पर बनाते हैं उस के लिए हमें बाहर से भी उपकरण मंगाने पड़ते हैं और इस के लिए 20 प्रतिशत के लगभग हम को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। उस के लिए हम कोशिश करते है कि हम को विदेशी मुद्रा मिले। काम अब अच्छा ख़ासा तेज़ी से चल रहा है।

आटोमेटिक एक्सचेंज के बारे में आप ने कहा तो हम आटोमेटिक एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा लगा रहे हैं। ऐसी जगहों पर, जहां टेलीफोनों की संख्या ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। 1000 के आसपास जब वह हो जाते हैं तो हम आटोमेटिक एक्सचेंज ज़रूर लगाते है। लेकिन छोटे छोटे देहातों या कस्बों में जब हम टेलीफोन लगाते हैं तो वहां SAX के वह छोटे एक्सचेंज लगाते हैं बाक़ी जब वह 1000 के आसपास हो जाते हैं तो हम बड़े MAX आटोमेटिक एक्सचेंज लगाते है और इस हिसाब से लगाते जा रहें है। यह ठीक है कि आपरेटर्स के बारे में कुछ शिकायतें रहती हैं। लेकिन इस का कारण यह नहीं है कि उन के पास काम ज्यादा है, कई बार उन में काफी गैरहाजिरि भी होती है। बाक़ी जहां काम ज्यादा हो और स्टाफ की कमी हो तो उस को हम देखते हैं और स्टाफ को पूरा करने की कोशिश करते हैं।

श्री यज्ञ दत्त शर्मा : लुधियाना के लिए मैं ने एक पटिकुलर सवाल किया था। लुधियाना देश का तथा उत्तरी भारत का एक बहुत बड़ा इडस्ट्रियल सेंटर है उस के लिए मंत्री जी ने जवाब नही दिया।

श्री शेर सिंह : लुधियाना में हम बड़ा आटोमेटिक एक्सचेंज लगाने वाले हैं। उस के लिए सामान भी पहुंच रहा है। भवन का निर्माण भी हो चुका है और उसे जल्द से जल्द लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं।

श्री यज्ञ दत्त शर्मा : कितने समय तक वह लग जायेगा ?

श्री शेर सिंह : अवधि बतलाना जरा मुश्किल है बाकि जब सामान आजायेगा तो सामान आने के 6 महीने बाद हम उसको चालू कर देगें।

श्री गा० शं० मिश्र : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में यह टेलीफोन कनैक्शन की कितनी ऐप्लीकेशंस पेंडिंग हैं विशेष कर ओवाईटी के अन्तर्गत कितनी ऐप्लीकेशंस पेंडिंग हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अभी उन्होंने बतलाया है।

श्री शेर सिंह : अभी मध्यप्रदेश में अपना टेलीफोन लगाओ योजना के अधीन टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन-पत्रों की संख्या सम्बन्धी प्रश्न के समय माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे बाकी वैसी चार ऐप्लीकेशंस पेंडिंग हैं और वह दूर के हैं इस लिए पेंडिंग हैं। तीन रायपुर में है और एक जबलपुर में है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवचरण लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल मुझे से ख़ास ताल्लुक रखता है। मैं ने कई साल से अपने वहां टेलीफोन कनैक्शन लगाने के लिए लिखा हुआ था। आगरे में एक चावली गांव है जहां कि डाकखाना चावली है जहां का कि मैं रहने वाला हूं, वहां पर टेलीफोन कनैक्शन लगाने के लिए दो साल पूर्व भूतपूर्व मंत्री डा० राम सुभग सिंह ने मुझे आश्वासन दिया था और वर्तमान मंत्री जी का भी इस सम्बन्ध में आश्वासन मुझे इसी महीने मिल चुका है तो क्या मैं आशा करूं कि वह अब बिना विलंब के लग जायेगा या अभी भी उस के लगने में दो, चार साल का समय लगेगा ?

श्री शेर सिंह : जो अश्वासन माननीय सदस्य कहते हैं कि दिया गया है उस आश्वासन को पूरा किया जायेगा।

जहां तक माननीय सदस्यों को टेलीफोन देने का प्रश्न है उस में जो देहात में रहते हैं उन को यह दूर टेलीफोन ऐक्सचेंज (long distance connections) के सम्बन्ध में हम को कठिनाई है। इसलिए जो अब नियम बना है माननीय सदस्यों को टेलीफोन देने के लिए सरकारी खर्चे से उस में एक शर्त रक्खी है कि जहां टेलीफोन ऐवेलेबुल हैं, उस का मतलब है कि लोकल ऐरिया में जो आते हैं, उस से बाहर जरा दूर के हैं, उस का खर्चा बर्दाश्त करने का उस के अन्दर कोई विधान नहीं है। वह अगर प्रबन्ध हो जाय तो हम दूर के टेलीफोन भी दे सकते हैं।

श्री मीठा लाल मीना : मैं मंत्री महोदय का ध्यान राजस्थान के भरतपुर-आगरा और बयाना-आगरा के बीच स्थित क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं जहां महीने में बीस दिन यह तांबे के तार की चोरियां होती हैं। जब यहां उधर ध्यान आकर्षित किया जाता है तब मंत्री महोदय की तरफ़ से जवाब दे दिया जाता है कि वहां पर इंतजाम किया जा रहा है पुलिस को सतर्क किया जा रहा है लेकिन अब भी हालत वही है और महीने में बीस रोज़ तांबे के तार की चोरियां हो जाया करती हैं। दूसरी चीज़ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह टेलीफोन के कनैक्शन जो आप के यहां से दिये जाते हैं तो उस बारे में प्राय: बड़े बड़े शहरों को ही प्राथमिकता दी जाती है, गांवों को यह कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस बारे में छोटे छोटे कस्बों और गांवों की ओर भी ध्यान देंगे या केवल बड़े बड़े शहरों की तरफ़ ही आप का ध्यान जाता रहेगा ? छोटे छोटे कस्बों की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री शेर सिंह : गांवों की तरफ से अब मांग आनी शुरू हो गई है। पहले वहां से टेलीफोंस की मांग नहीं होती थी बाक़ी जैसा मैं ने बतलाया अब गांवों और छोटे छोटे कस्बों की ओर भी इस विषय में हमारा ध्यान जा रहा है और हम अधिक से अधिक छोटी जगहों पर, गांवों आदि में टेलीफोन देने की कोशिश करते हैं।

जहां तक तांबे के तार की चोरी का सवाल है यह सही है कि इस की चोरियां उस लाइन पर रोजबरोज बढ़ती जा रही हैं। इस बारे में हम ने सतर्कता बर्ती है और राज्य सरकारों को भी सचेत किया है लेकिन तो भी वह चोरियां रुक नहीं पायी हैं। इस के लिए अब हम यह कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी उन तमाम कौपर वाएर्स को हम अल्यूमीनियम वाएर्स से रिप्लेस कर दें। हम उन तांबे के तारों को अल्यूमीनियम के तारों में बदल रहे हैं ताकि यह चोरियां न हों और काम ठीक से चलता रहे।

SHRI S. KUNDU : A large quantity of the components of the telegraph and telephone equipments are being imported from abroad. Since the imported items do not arrive at the right time the fixation of telephones and the installation of exchanges are delayed. Has the Ministry got any definite programme to achieve self-sufficiency in all the components of the telegraph and telephone equipments ?

SHRI SHER SINGH : Our difficulty is that we have to import certain raw materials which are not available in our country. We do not import many components. It is only those components which if we manufacture here, would be more costly, it is only those components which we import. Otherwise, we generally import raw materials, copper wire, nickel etc. We have now got World Bank and Canadian loans for manufacturing more exchange equipment etc. for starting new exchanges. All those items which we can produce here, we are already producing. Our difficulty is about raw material, not about components.

श्री भा० दा० देशमुख : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं मेम्बर्स को अपने कार्य सुविधा के लिये उन के रैंजीडेशियल हैडक्वार्टर पर जो टेलीफोन की फेसिलिटी दी गई है उस में 80 प्रतिशत मेम्बर गांवों से आते हैं और वहा ऐंक्सचेंज की सुविधा नहीं है । तो क्या इस के बारे में सोचा जायेगा कि उन को वहां पर ऐंक्सचेंज की सुविधा पहुंचाने में प्रायरिटी सरकार दे?

श्री शेर सिंह : जहां तक इस विभाग का सम्बन्ध है हम तो देने को तैयार हैं लेकिन जो जगहें ऐंक्सचेंज से दूर हैं वहां से इस सुविधा को पहुंचाने के लिये जो अतिरिक्त खर्चा पड़ेगा यदि उस के लिये कुछ प्रबन्ध हो जाये तो हम को कोई एतराज नहीं है ।

श्री देवराव पाटिल : दूर के क्या माने हैं?

श्री शेर सिंह : पांच किलोमिटर तक तो लोकल ऐंक्सचेंज का एरिया होता है । उस से बाहर दूर का हो जाता है ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : अभी मंत्री जी ने कहा कि संसद सदस्यों को अपनी कांस्टीट्यूऐंसी में टेलीफोन लगाने की सुविधा दी गयी हैं, उस के मुताबिक यदि नजदीक तक टेलीफोन कनेक्शन्स आ गये हैं तो लगा दिये गये हैं । लेकिन क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि मैं ने अपने चुनाव क्षेत्र में, जो मेरा आफ़िस है वहां पर टेलीफोन कनेक्शन लगाने के लिये निवेदन किया था । हमारे आफ़िस से एक, डेढ़ फ़र्लांग तक टेलीफ़ोन कनेक्शन आ गये हैं, फिर भी किसी न किसी बहाने हमारे दफ्तर में टेलीफोन नहीं लगाया जा रहा है, और ऐसा मालूम होता है . . .

अध्यक्ष महोदय : इंडिविजुअल क्वेश्चन के बारे में लिख भेजिये, सवाल क्यों पूछते हैं ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : जहां तक बिहार का सवाल है वह दिया तले अंधेरे वाली बात है क्यों कि मंत्री महोदय उसी प्रान्त से आते हैं । तो अखिल भारतीय आधार पर जो टेलीफ़ोन की संख्या है उस में बिहार का औसत बहुत ही कम है । क्या इस के लिये कोई विशेष कोशिश की जायेगी ताकि अखिल भारतीय स्तर तक बिहार पहुंच जाये?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : बिहार के लिये खास तौर पर नहीं लेकिन हर पिछड़े इलाके के लिये कोशिश हो रही है । आप ने बताया हम को ताज्जुब होता है कि आप को टेलीफ़ोन नहीं मिला । आप इस के लिये मुझे लिखेंगे तो मैं जांच कराऊंगा ।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : माननीय मंत्री जी ने कहा कि 4.4 लाख लोगों की लिस्ट है जिन को टेलीफ़ोन नहीं मिला । मैं जानना चाहता हूं कि इन में कितने लोग देहात के और कितने शहर के हैं? और जब टेलोफ़ोन आ जायेंगे तो उनका जो परसेन्टेज है उस को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से आप अलाटमेंट करते हैं, क्यों कि शहर वालों का बहुमत होता है इसलिये गांवों वालों को टेलीफ़ोन नहीं मिल पाता है ।

दूसरी बात यह है कि क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी स्कीम है कि गांवों के लोगों को जो कि 80 फ़ीसदी गांवों में रहते हैं उन के

लिये कम से कम पांच किलोमिटर के अन्दर हर जगह पी० सी० ओ० हो ताकि गांवों के लोग उस का पूरा फ़ायदा उठा सकें? अगर ऐसी कोई स्कीम है तो उस की तफ़सील क्या है? अगर नहीं है तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

श्री शेर सिंह : 4.4 लाख लोगों की वेटिंग लिस्ट में देहात के लोगों की संख्या कम होगी, शायद चन्द आदमी ही होंगे क्यों कि ज्यादातर शहरों में ही मांग है । देहात में किसानों की तरफ़ से भी मांग होने लगी है और कुछ जगहों पर हम ने टेलीफ़ोन देना शुरु किया है । यह ठीक है कि देहात में बहुत कम दे पाये । हम कोशिश कर रहे हैं कि देहात में और ज्यादा टेलीफ़ोन दे सकें । जैसे जैसे मांग बढ़ेगी हम इस की कोशिश करेंगे । जहां तक योजना के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, ऐसी कोई योजना नहीं है कि पांच किलोमिटर के अन्दर हर जगह पी० सी० ओ० लग जाये । जैसे जैसे मांग आयेगी उस पर विचार किया जायगा ।

SHRI M. N. NAGHNOOR : It is a matter of pride that technically we are self-sufficient and we do not want anything to go ahead with greater production to meet the country's demand. On the other hand, there is almost a famine for the installation of telephone equipment. So, government must take some positive steps. The Bangalore industry has been able to give a very good account of itself in the matter of telephone production. Why should the government not take steps to produce more equipments, if necessary even with the co-operation of the private industries, to meet the demands of the country?

SHRI SHER SINGH : The only limiting factor for producing more equipments is the paucity of foreign exchange. We have to import raw materials. Out of the total value of the output of the telephone industries about 20 per cent is in the form of foreign exchange. That difficulty will remain even if we hand it over to the private sector. It is not because of lesser capacities in our factories that we are not producing more equipments. Our difficulty is the want of resources to get the raw materials from abroad.

SHRI G. S. REDDY : In view of the shortage of telephone equipments, are there any plans to set up further industries besides the one in Bangalore?

SHRI SHER SINGH : Yes, Sir. We are building up one factory at Naini, for which administrative approval and financial sanction has been given. We are proposing to set up another instruments factory also. So, we propose to set up two more factories.

SHRI HEM BARUA : Since the telephone has become a prestige symbol with some and with some it is a matter of necessity, may I know if the Government are aware of the fact that there is a lot of financial corruption in the matter of allotment of telephones to persons and, if so, what steps the Government have taken to do away with this corruption in the matter of allotment of telephones?

SHRI SHER SINGH : The telephone is becoming a necessity now; it is not a symbol of prestige...

SHRI HEM BARUA : With some, it is a prestige symbol and, with some, it is a matter of necessity. That is what I have said.

SHRI SHER SINGH : Now, it has ceased to be a symbol of prestige. It has become a necessity. If the hon. Member has some instances in which the corruption has taken place, he may pass on the information and I will, certainly, look into it.

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : The hon. Member must know that the allotment of telephones is made by the Telephone Advisory Committee. In small districts also, practically we have got Telephone Advisory Committees. It is for them to decide the allocation of telephones.

SHRI HEM BARUA : It is not that. The bureaucrat sitting in the office decides the allotment of telephones.

श्री रणधीर सिंह : हमारी सरकारी बैंचेज पर जो बड़े वजीर और छोटे वजीर बैठे हैं वह दोनों किसान हैं, फिर भी वह साढ़े चार लाख गांवों में से दस हजार आबादी वाले गांवों को टेलीफ़ोन देने की बात कर रहे हैं । यह सरकार जब 5 हजार की आबादी पर बुक पी० सी० ओ० खोल रही है तब क्या वह टेलीफ़ोन के मामले में कुछ रिलैक्सेशन करेगी क्या वह एक हजार आबादी वाले गांवों को पी० सी० ओ० देगी

क्योंकि वहां पर अफ़सर भी रहते हैं, बड़े किसान रहते हैं, एम० ए० बी० टी० पास लोग रहते हैं या फ़िर अगर उस ने पांच हजार की शर्त को बिल्कुल ही रख दिया है तब क्या वह आस पास के गांवों को इकट्ठा कर के हर 5,000 की आबादी पर एक पी० सी० ओ० देगी। मैं जानना चाहता हूं कि जब वह शहर में इस तरह का कोई बार आबादी पर नहीं लगाती है तब फिर देहात में क्यों इस तरह का बार लगाती है?

श्री रणधीर सिंह : गांवों में टेलीफ़ोन की मांग बढ़ रही है। लेकिन अगर किसी छोटे गांव में जहां पर उस का काम कम हो टेलीफ़ोन लगाया जाये तो उस से घाटा होता है। इस से हम को कठिनाई पड़ती है। जब तक इस घाटे को पूरा करने का कोई तरीका सामने नहीं आता तब तक हम इस काम को हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन अगर सदन फैसला करे और इसकी इजाजत दे कि हम घाटा उठा कर लोगों को टेलीफ़ोन दें तो हम उस को कर देंगे। अगर सदन की ओर से पैसे की व्यवस्था हो जाये तो ऐसा किया जा सकता है।

श्री रणधीर सिंह : मिनिस्टर साहब 5,000 की लिमिट को रिलैक्स करने के लिये तैयार हैं या नहीं?

Fishing Harbours at Bombay, Cochin, Madras, Visakhapatnam and Tuticorin

\+

*905. SHRI P. GOPALAN :
SHRI VISWANATHA MENON :
SHRI NAMBIAR :
SHRI A. K. GOPALAN :
SHRIMATI SUSEELA GOPALAN :

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the number and names of the fishing harbours in India ;

(b) whether the Government had drawn up any detailed plans for large fishing harbours at Bombay, Cochin, Madras, Vishakhapatnam and Tuticorin ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) if not, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) to (d). A statement is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

(a) The number of harbours at which basic facilities for fishing vessels have been provided is 30 as detailed in the attached list.

(b) to (d). Detailed plans and estimates have been prepared and financial sanction issued for fishing harbours at Bombay, Madras and Tuticorin. Plans and estimates for Cochin have been received from the Port Trust and are under consideration. Plans and estimates for Visakhapatnam are under preparation. Details of harbours sanctioned are given below :—

	Bombay	Madras	Tuticorin
1. Harbour construction cost	Rs. 453 lakhs	Rs. 389 lakhs	Rs. 210 lakhs
2. Length of quay .	800 metres.	575 metres	824 metres
3. No. of vessels to be accommodated.	250 vessels less than 14m overall length and 65 vessels between 15-37m O.A.L.	500 vessels less than 14m OAL & 50 vessels between 15-37 m O.A.L.	250 vessels less than 15m OAL and 65 vessels between 15-37m OAL
4. Estimated addl. quantity of fish landings.	40,000 tonnes	40,000 tonnes	22,500 tonnes